was prepared and sent to the Government for posing to OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) loan assistance from the Middle East countries. In July, 2001, the Tamil Nadu Government prepared the necessary project report and sent it for posing to JBIC (Japan Bank of International Co-operation) for loan assistance for the implementation of the project. Recently, the Government of Tamil Nadu and the Government of Malaysia expressed their desire of co-operating in establishing the Hogenakkal Water Supply and Sanitation Project in Dharmapuri District, and the Memorandum of Understanding has been sent to the Government of India for its clearance. I request the Government, through this House, for an early clearance of the Memorandum of Understanding sent by the Tamil Nadu Government, in order to implement the Hogenakkal Water Supply and Sanitation Project. Thank you, Madam.

Closure of NTC Mills

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, विदर्भ में कम्पोजिट मिलें बंद होने से वहां के मजदूरों की बढ़ती बेरोजगारी की समस्या की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । महोदया, विदर्भ में 11 कम्पोजिट मिलें हैं जिनमे 5 मिलें NTC की हैं और 4 मिलें महाराष्ट्र सरकार की हैं । ये चारों मिलें बंद हो गईं जिनमें 6,000 मजदूर काम करते हैं । इन सभी मजदूरों को VRS देने का वायदा किया गया था लेकिन दिया नहीं गया । NTC की 5 में से 3 मिलें, जिनमे नागपुर की माडल मिल शामिल है, जिसमें 1,600 मजदूर काम करते हैं, उसे भी बंद करने का ऐलान किया गया है । बाकी 3 मिलें चालू हैं जो कोऑपरेटिव सैक्टर में हैं । चौथी श्रेणी मे प्राइवेट सैक्टर की लगभग 5 मिलें हैं जो चालू हैं जिनमें कुछ कॉटन मिलें हैं और कुछ पॉलियस्टर धागा बनाने वाली मिलें हैं ।

महोदया, इन मिलों को बंद करने का मुख्य कारण गैर-संचालन व्यवस्था है लेकिन सरकार इसका कारण पैसा न होना बता रही है । मेरा अनुरोध है कि इन सभी मिलों को बंद न करके इन्हे चलाना चाहिए तथा इनकी surplus assets को बेचकर उस पैसे को modernisation के काम मे लगाया जाए क्योंकि मिलें बंद करना कोई उचित व्यवस्था नही है।

महोदया, मेरा मत है कि जो मजदूर VRS लेना चाहते हैं, उन्हें यह सुविधा देकर बाकी सभी लोगो को रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया जा सके क्योंकि विदर्भ में बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये सभी मिलें जो प्राइवेट लोगो की थीं, उन्हे NTC ने और महाराष्ट्र सरकार ने अपने हाथ में लिया था। उनकी करोड़ो रुपयों की प्रॉपर्टी को बेचकर बिल्डर्स को देने का जो काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है, यह ठीक नही है । इसलिए ये मिलें चालू रहनी चाहिए, यह मेरी मांग है ।

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Madam, I wish to associate myself with what the hon. Member has said. The Ministry should do something; the workers are dying; the mills are closed.